सार

2400 मेगावाट क्षमता वाले टिहरी बाँध का निर्माण 1976 में शुरू हुआ एवं 2006 में बनकर तैयार हो गया। इस बाँध के साथ लगभग 200 साल पुराने ऐतिहासिक टिहरी शहर सहित 125 गांव जलमग्न हो गए। इसके कारण लगभग एक लाख की आबादी विस्थापित हुई। 1815 में महाराजा सुदर्शन शाह द्वारा बसाया गया यह शहर टिहरी रियासत की राजधानी भी रह चुका है।

टिहरी बाँध के खिलाफ सबसे पहले 1969 में क्षेत्र की सांसद राजमाता कमलेंदुमति शाह ने संसद में आवाज उठाई। 1972 में जब बाँध की रूपरेखा तय की गई तब से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया था। 1976 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1978 में वीरेंद्र दत्त सकलानी की अध्यक्षता में आंदोलन को गति देने के लिए 'टिहरी बाँध विरोधी समिति' का गठन किया गया। बाद में उनका स्वास्थ खराब रहने लगा जिस कारण 1989 में चिपको आंदोलन से चर्चित हुए सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बाँध आंदोलन से जुड़ गए। बहुगुणा ने टिहरी बाँध परियोजना का साल 2004 तक सक्रिय रूप से विरोध किया। टिहरी बाँध से प्रभावित लोग आज भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उत्तराखण्ड की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का आधार महिलाएं हैं। 'टिहरी बाँध आंदोलन' में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आजादी के बाद नेहरू सरकार के कंधों पर देश के विकास की जिम्मेदारी थी। इसके लिए सरकारों को बहुउद्देशीय बाँध परियोजनाओं के निर्माण की जरूरत महसूस हुई ताकि देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही अन्य उद्देश्य भी थे जैसे देश में खुलने वाले उद्योग धंधों को बिजली-पानी उपलब्ध कराया जा सके, जल संकट वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा सके एवं देश में फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके आदि। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाँधों को आधुनिक तीर्थ की भी संज्ञा दी है।

शुरुआती दौर में इन बहुउद्देशीय बाँध परियोजनाओं को बहुत अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जनता देश के विकास के लिए त्याग करने को तत्पर थी। सरकारें भी यही मानती थीं कि देश-समाज के सामूहिक हित की खातिर कुछ लोगों को बलिदान देना ही चाहिए। लेकिन इन परियोजनाओं से स्थानीय जनता कोई खास लाभ नहीं मिला, बल्कि कइयों को तो मूलभूत अधिकारों से भी वंचित होना पड़ा है।

बाँध परियोजनाओं के विस्थापितों का ना ही ठीक से पुनर्वास हो पाया और ना ही उचित मुआवजा मिल पाया। मूल जीवन परिस्थितियों से भिन्न वातावरण में रहने के कारण आर्थिक, सांस्कृतिक क्षति और मानसिक विलगाव का सामना करना पड़ा। शुरुआती बाँध परियोजनाओं से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत होने के बाद जनता ने नई बनने वाली बाँध परियोजनाओं का विरोध तीव्र किया।

स्थानीय जनता के साथ-साथ बड़े-बड़े वैज्ञानिक, पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी बाँधों के निर्माण पर सवाल उठाने लगे। एक बड़ी आबादी को उसके निवास स्थान से अलग कर, जंगलों एवं उपजाऊ जमीनों को डुबोकर किया जाने वाला विकास सवालों के घेरे में आता रहा। इतना सब होने के बावजूद बाँध अगर स्थाई होते तो इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन बाँधों की एक निश्चित उम्र होती है। एक शताब्दी बीतते-बीतते इनमें गाद भर जाती है और इसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के शब्दों में कहें तो बाँध स्थाई समस्या का अस्थाई हल हैं। वह सुझाव देते हैं कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाएं जो कि स्थाई बाँध का काम करते हैं। वे बाँधों को जल संग्रहण का अवैज्ञानिक तरीका बताते हैं।

देश भर में जनता बड़े बाँधों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। सबसे अधिक चर्चित बाँध विरोधी आंदोलन 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' रहा है जिसकी नेता मेधा पाटेकर हैं। टिहरी बाँध से प्रभावित लोग अभी भी अपनी माँगों को लेकर आंदोलनरत हैं। एक लोकतांत्रिक समाज को बचाए रखने में मीडिया में भूमिका बहुत अहम होती है। टिहरी बाँध आंदोलन की जनता के पक्ष को कई पत्र-पत्रिकाओं ने स्थान दिया।

मीडिया के सहयोग से इस आंदोलन की गति को प्रोत्साहन मिलता रहा। संसाधनों की कमी के बावजूद स्थानीय इसमें स्थानीय मीडिया की अहम भूमिका रही। समाचार-पत्रों ने टिहरी बाँध आंदोलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया है। जैसे इसके पर्यावरणीय पहलू, विस्थापन की समस्या, पुनर्वास की मांग, रोजगार की समस्या, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आंदोलकारियों के साथ की जाने वाली दमनात्मक कार्यवाहियाँ इत्यादि। इस दौरान बाँध समर्थकों ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसका चेहरा रहे सुंदरलाल बहुगुणा की छवि को प्रभावित करने की भी कोशिश की। हालांकि बाँध समर्थकों का पक्ष भी मीडिया में सामने आता रहा लेकिन उसका प्रतिशत कम रहा।

टिहरी क्षेत्र की अधिकांश जनता बाँध के विरोध में रही है। कुछ लोग जो बाँध के पक्ष में या तटस्थ थे वे भी पुनर्वास की स्थितियों से असंतुष्ट हैं। बाँध निर्माण के फायदों के सबंधं में अधिकांश लोगों का मानना है कि किए गए वादों के मुताबिक उनको कोई लाभ नहीं हुआ। बल्कि इसका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

लगभग तीन दशकों तक सक्रिय तौर पर चले टिहरी बाँध विरोधी आंदोलन के संबंध में यह सवाल भी उठाया जाता है आखिरकर बाँध का निर्माण तो हो ही गया फिर इससे क्या फायदा हुआ। लेकिन टिहरी बाँध, नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलनों ने बड़े बाँधों बड़े बाँधों के खिलाफ एक बहस को जन्म दिया एवं बड़े बाँधों के औचित्य पर सवाल उठाया। जिससे भविष्य में इस तरह की विकास परियोजनाओं का निर्माण करने से पहले स्थितियों की बेहतर तरीके से जांच की जा सके। बाँध आंदोलनों के मुद्दों की इस बहस को व्यापक रूप में देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।